







## संघ प्रमुख मोहन भागवत की चिंता

इंदौर में कैंसर के मरीजों के किफायती इलाज के लिए शुरू किए गए 'गुरुजी सेवा न्यास' के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश में चिकित्सा और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर चिंता जताते हुए कहा कि दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम लोगों को 'सहज, सुलभ, सस्ती और सहदद्य' सुविधाएं मुहैया कराई जाना बक्त की मांग है। संघ प्रमुख ने इस मौके पर एक समारोह में कहा कि अच्छी चिकित्सा और शिक्षा की सारी योजनाएं आज समाज के हर व्यक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि दोनों क्षेत्रों की (अच्छी) सुविधाएं आम आदमी की पहुंच और आर्थिक सामर्थ्य के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि पहले चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्रों में सेवा की भावना से काम किए जाते थे, लेकिन अब इनका भी व्यवसायीकरण हो रहा है। संघ प्रमुख ने जोर देकर कहा कि जनता को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्रों में सहज, सुलभ, सस्ती और सहदद्य सुविधाएं मुहैया कराई जाना बक्त की मांग है। भागवत ने देश में कैंसर के महंगे इलाज पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज की अच्छी सुविधाएं केवल आठ-दस शहरों में मौजूद हैं जहां देश भर के मरीजों को बड़ी धनराशि खर्च करके जाना पड़ता है। भागवत ने आम लोगों के लिए चिकित्सा और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं पेश करने के वास्ते समाज के सक्षम और समर्थ लोगों से आगे आने का आह्वान किया। संघ प्रमुख ने कहा कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) जैसे शब्द बेहद तकनीकी और औपचारिक हैं। सेवा के संदर्भ में हमारे यहां एक शब्द है-धर्म। धर्म यानी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना। धर्म समाज को जोड़ता है और समाज को उन्नत करता है। भागवत ने यह भी कहा कि पश्चिमी देश चिकित्सा के क्षेत्र में अपने एक जैसे मानक दुनिया के अन्य हिस्सों के देशों पर लागू करने की सोच रखते हैं, लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में मरीजों का उनकी अलग-अलग प्रकृति के आधार पर इलाज किया जाता है। पिछले दिनों देश के उच्चतम न्यायालय ने महंगी होती शिक्षा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब शिक्षा क्षेत्र भी एक व्यापार बनकर रह गया है। निजी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय हो या निजी अस्पताल यह सब एक जन साधारण की पहुंच से बाहर हैं। सरकारी अस्पतालों और स्कूलों के गिरते स्तर के कारण जन साधारण की स्थिति भवंतर में फंसे इंसान की तरह है। जितना वह भवंतर से निकलने की कोशिश करता है वह और ढूबता चला जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उपरोक्त सच्चाई को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा और चिकित्सा के व्यवसायीकरण को लेकर चिंता प्रकट की है। देश में जन साधारण की स्थिति को देखते हुए संघ प्रमुख भागवत की बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर काफी काम हो रहा है। अभी काफी होने वाला भी है। शिक्षा क्षेत्र की तरह चिकित्सा क्षेत्र में भी संघ को राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होकर आगे आना चाहिए। 'परमार्थ ही धर्म है', इसी को अपना ध्येय वाक्य बनाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सनातन धर्म के संदेश को देश व दुनिया के सामने रखते हुए सनातन धर्म के प्रति जो भ्रम व भाविताएँ हैं, उन्हें तप्त भी कर सकेंगा।

खरीफ फसलों में इस बार बाजरा का उत्पादन  
गिरेगा ,किसान बेहाल, परेशान

अजय दीक्षित  
भारत में खरीफ फसलों के रूप में बाजरा मूँग, उड्ड, सोयाबीन, रागी, आदि मानसून सीजन में होती हैं। लेकिन इस बार अत्यधिक बारिश और बाढ़ चलते विशेषकर उत्तर भारत, में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, में बाजरा की फसल लगभग समाप्त हो गई है। भारत में लगभग 80 लाख हैक्टेयर भूमि में यह फसल उगाई जाती है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक 42 लाख हैक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 22, मध्य प्रदेश में 9.5 और गुजरात 10 लाख हैक्टेयर भूमि बाजरा की बोवनी होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, औडिशा, को मिलकर 118000 से अधिकतम 1300 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जाता है इस बार किसान 15 जून के आसपास तीव्र मानसून आने के कारण राजस्थान, गुजरात, मध्य, उत्तर प्रदेश में या तो फसल की बोवनी नहीं कर पाए या बोवनी हो भी गई तो लगातार बारिश कारण फसल गल गई। बाजरा एक ऐसी फसल है जो बहुत कम पानी में हो जाती है चंबल क्षेत्र में कहावत है कि बाजरा के तो कान में भी पानी की कुछ बृद्ध चली जाय तो फसल हो जाएगी। बाजरा उहाँ इलाकों की फसल थी जहाँ सिंचाई के साधन नहीं थे। ब्रिटिश गजट में उल्लेख है कि 1912 में उत्तर भारत में बाजरा जोए, मूँग, रागी, उड्ड, ग्वार, मूँगफली की खेती होती थी। 1912 में जब भयंकर सूखा पड़ा तो लोगों के पास अनाज नहीं था। और 30 की आबादी इस सूखे के चलते काल के गाल में समा गई थी। इसी प्रकार 1930 का सूखा ऐसा पड़ा था कि गुजरात में अनाज के बदले

अपने गहने, बच्चे बेच दिए थे जो बालिंग थे।  
बाजरा उत्तर भारत का ऐसा अनाज है जो साल भर चलता है उसी के साथ दालें भी होती हैं किसान का मुख्य भोजन इन चीजों से ही बनता है। सबलगढ़ मध्य प्रदेश के गरीब किसान मनीष रावत कहते हैं कि इस बार पशुओं के लिए चारा के भी लाले पड़े हैं बाजरा मूँग उड़द अति वर्षा के कारण नष्ट हो गई है। बाजरा की फसल मनुष्यों से तो जुड़ी हुई है लेकिन यह पशुओं का हाहा चारा भी है। सिंतंबर से फरवरी तक पशुओं को बाजरा की करब ही चुनी में मिलकर दी जाती है दुधारू गायों, भैंसों को घास के साथ, बाजरा के अतिशेष भी दिए जाते हैं बाजरा मध्य जन में वो कर ८० से ९० दिन

आजादी का नाम दें जाता है जिसका मत्तू न कर सकता है। इसका मत्तू न कर सकता है। यहाँ में काटा जा सकता है यानी आषाढ़ से कुंवार माह में हो जाता है।

आजादी के बाद और कुछ इलाकों में अंग्रेजों ने भी सिंचाई परियोजना बांध निर्माण किए परगर आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री ने स्व जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में रावी व्यास, सतलज, सिंध, चंबल, गंगा, यमुना, गोमती, कावेरी कृष्णा गोदावरी, नर्मदा, बेतवा, केन, पार्वती, महानदी, दामोदर वैली, गांधी सागर, हीराकुण्ड, बांध निर्माण किए गए। इनमें से लाखों किलोमीटर नहर बनाई गई जो भारत में हरित क्रांति का कारण बने। किसान रवि की फसल भी लेने लगे हैं। कनाडा विश्व का सबसे बड़ा कृषि हब है। लेकिन वहाँ की सरकार किसानों को बीज, खाद, पानी, वेयरहाउस, मुफ्त में देती है। लेकिन अपने देश में अभी वह समय नहीं आया है।

# सार्वजनिक मार्केट प्लेस की पारदर्शी दशक यात्रा

उमेश चतुर्वेदी

नौ अगस्त की तारीख हमारे इतिहास में अगस्त क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। भारत से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने वाले निर्णायक 'भारत छोड़ो आंदोलन' की शुरूआत इसी दिन हुई। यह तारीख इतिहास में एक और वजह से भी महत्वपूर्ण बन गई है। इसी दिन साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक और सरकारी खरीद में पारदर्शिता की शुरूआत के लिए सरकारी मार्केट प्लेस यानी बाजार की शुरूआत 'जीईएम यानी गवर्नरमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस शुरू किया। जीईएम का मूल मंत्र है, पारदर्शी, समावेशी और कुशल शासन की आधारशिला। इस ऑनलाइन सार्वजनिक और पारदर्शी बाजार ने नौ साल की आधिकारिक यात्रा पूरी कर ली है और एक दशक की यात्रा के लिए आगे बढ़ चुका है।

प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'। इसके सीईओ मिहिर कुमार कहते हैं कि जीईएम प्रधानमंत्री के इसी दृष्टिकोण को साकार कर रहा है। मिहिर कुमार के अनुसार, सिर्फ नौ साल की ही अवधि में यह पोर्टल देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल खरीद मंच बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में इस पोर्टल पर महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, मध्यम और लघु उद्योग, शिल्पकारों, स्थानीय कारीगरों और दिव्यांगजनों समेत पूरे देश के विक्रेताओं और सेवाप्रदाताओं के सशक्तीकरण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस पोर्टल या ऑनलाइन बाजार पर विक्रेताओं के लिए जमानती राशि रखने का प्रावधान है। लेकिन अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। मिहिर कुमार के अनुसार, इसकी वजह से विशेषकर छोटे निर्माताओं और कारोबारियों को ज्यादा फायदा होना है। सार्वजनिक और समकारी खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने पारदर्शी और समावेशी ऑनलाइन मार्केट की अवधारणा प्रस्तुत की थी। जीईएम उसी अवधारणा का विस्तार है। इसके कामकाज शुरू करने के बाद केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों के लिए इसी पोर्टल के जरिए खरीद अनिवार्य कर दिया गया। अब जीईएम प्रबंधन का जोर राज्य सरकारों

की खरीद को भी इसी के जरिए जस्ती बनाने पर है। अपने दस साल में राज्यों पर फोकस करने की दिशा में जीईएम प्रबंधन ने तैयारी की है। जीईएम को उमीद है कि उनके जरिए हो रही सार्वजनिक खरीद में जिस तरह सार्वजनिक क्षेत्र को बचत हो रही है, उसकी वज्र से राज्य सरकारों भी इसकी ओर आकर्षित होंगी। वैसे राज्यों की उमीद से इसके जरिए खरीद होने भी लगी है। हालांकि उसकी मात्रा अब कम है। जीईएम के जरिए होने वाली खरीद में अब तक एनटीपी को जहां करीब दो हजार करोड़ की बचत हुई है, वहीं बैंक और बड़ोदा को 34 करोड़। इसी तरह भारतीय नौसेना ने भी पंद्रह करोड़ की बचत की है। जीईएम के अधिकारी तो इसे स्वीकार नहीं करते लेकिन जाहिर है कि यह बचत जहां खरीद में घपले की कमी से हुई वहीं सार्वजनिक मार्केट प्लेस पर उपलब्ध ढेरों और गुणवत्तापूर्ण सामग्री में मूल्यों को लेकर हुई प्रतिद्वंद्विता की वजह से हुई है।

जीईएम के सीईओ मिहिर कुमार के अनुसार, इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस ने सिर्फ खुद के दम पर साल 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ रुपये के सकल व्यापारिक मूल्य सार्वजनिक खरीद को न केवल सुव्यवस्थित किया है, बल्कि शासन में पहुंच, समानता और सशक्तीकरण को फिर से पारिभाषित किया है।

जीईएम ने अपने स्थापना के दसवें वर्ष का सूत्र वाक्य, सुगम पहुंच और समावेशन विषयों पर केन्द्रित किया है। मिहिर कुमार कहना है कि उसका यह सूत्र वाक्य सार्वजनिक खरीद को अधिक सुलभ और न्यायसंगत बनाने की दिशा में उनके संगठन की प्रतिबद्धता और पारदर्शी कामकाज को प्रदर्शित करता है। मिहिर कुमार यह कहते हैं कि वैसे तो ऑनलाइन खरीद के कई पोर्टल हैं। लेकिन सभी कारोबारी पोर्टल हैं, जबकि जीईएम मार्केट प्लेस है। वह एकाग्रता कारोबार नहीं करता, बल्कि पारदर्शी कारोबार का मंच उपलब्ध कराता है। जिसमें खरीदार और विक्रेता, दोनों का फायदा है।

जीईएम की कामयाबी ही कही जाएगी कि इसके जरिए अब तक करोड़ से ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। जिनके जरिए 4.81 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है। इस मार्केट प्लेस पर मौजूदा वित्त वर्ष

11हजार से ज्यादा प्रोडक्ट, 344 से ज्यादा सर्विस श्रेणी, 20 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोर्टल पर सबकुछ ऑटोमेशन में सॉफ्टवेयर संचालित है, कोई मैनुअल हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि जीएम के अधिकारी मानते हैं कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है और वह लगातार होती रहेगी। ताकि खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बरकरार रहे।

यह ठीक है कि अब विक्रेताओं के लिए जमानती राशि की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही जीईएम ने कई और सुधार शुरू किये हैं। इसमें विक्रेता के मूल्यांकन शुल्क को तारीक बनाना और लेनदेन शुल्क में उल्लेखनीय कमी करना भी समिल है। वेंडर चार्ज भी पहले की तुलना में 68 प्रतिशत से लेकर 92 प्रतिशत तक कम किए जा चुके हैं। इन सबकी वजह से यहां मिलने वाले 97 प्रतिशत ऑर्डरों को छूट मिल गई है। मिहिर कुमार कहते हैं कि उनकी कोशिश, विक्रेताओं को सशक्त बनाना, मध्यम और लघु उद्योगों बढ़ावा देने की है। इस दिशा में पहली बार विक्रेताओं और छोटे उद्यमों के लिए मजबूत सहायता द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।

जीईएम का कारोबार ना पासके बड़े, बाल्क दूर-दरीजे के इलाकों में स्थित कारीगरों, निर्माताओं, उद्यमियों और कारोबारियों को समावेशी मंच उपलब्ध कराना भी है। जीईएम के अधिकारी कहते हैं कि किंवदन्ति उनका ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि आदिवासी कारीगरों से लेकर तकनीक-संचालित स्टार्टअप तक हर उद्यम तक सार्वजनिक खरीद के अवसरों आसानी से पहुंच सकें। इस दिशा में इसके दिल्ली मुख्यालय में छह अगस्त को जीईएम विक्रेता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जीईएम के मंच पर देश के हर वर्ग के उद्यमियों, कारोबारियों और निर्माताओं को साथ लाने की कोशिश हुई। कागज रहित, वास्तविक समय के लेन-देन को सक्षम बनाने से लेकर स्वास्थ्य, खनन और बीमा में करोड़ों रुपये के अनुबंधों को सुगम बनाने तक, जीईएम ने नीति निर्माण और जमीनी स्तर की भागीदारी के बीच की खाई को पाठने की सफल कोशिश की है। (यह लेखक के अपने विचार है)

## सरकार की दूढ़ता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा

## गा. आरक्षना महाजन

अमरीका राष्ट्रपति डानल्ड ट्रूप ने भारतीय आयातों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कुल टैरिफ अब 50 प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रपति ट्रूप का यह कहना है कि यह कदम भारत द्वारा रूसी तेल की नियंत्रण खरीद के जवाब में उठाया गया है। इसके साथ ही भारत अमरीका के सबसे अधिक कर वाले व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया है। अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ 27 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा। इस वृद्धि से अमरीका को 40 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के भारतीय नियांत्रित प्रभावित होंगे, जिनमें ऑटो पार्ट्स, कपड़ा और परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात और सामान, आधूषण और समुद्री खाद्य आदि शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों को टैरिफ वृद्धि से छूट भी दी गई है, जिनमें शामिल हैं, फार्मास्युटिकल्स, तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा उत्पाद जैसे तेल, गैस और एलएनजी, तांबा इत्यादि। यदि अमरीकी टैरिफ प्रभाव डालेंगे भी, तब भी अमरीका को भारत का नियांत्रित अधिकतम 5.7 अरब डॉलर ही गिरेगा। लेकिन आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि 2022 और 2024 के बीच भारत को रूस से तेल आयात करके 33 अरब डॉलर का फायदा हुआ। यानी यदि नफा नुकसान देखें तो भारत को रूस से तेल आयात से इतना फायदा है कि उसे अमरीकी टैरिफ की परवाह करने की जरूरत नहीं। इस बीच टंप ने चीन सहित रूसी तेल खरीदने वाले अन्य देशों पर एक अलिंग 'विनियंत्रण अनियंत्रण'

नकता यह ह कि भारत उत्तराधिन में आत्मनिर्भरता करण खरीदने और जहां उसे सबसे सस्ते दामों पर बेबद्द है, ताकि घरेलू बना रहे। इस बीच भारत स्पृहूँकि अगर अमरीका तरह की धमकियां देकर कता है, तो उसे अपनी रने की जरूरत है। आज यहले जैसा भारत नहीं है। एक वैश्विक शक्ति के ओपेशन सिंदूर के दौरान हकि हम सामरिक दृष्टि से अमरीका से आने वाले सामानों पर शुल्क बढ़ाव करें। हाल के दिनों में, जब राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पारस्परिक टैरिफ लगाए जाने के बाद, भारत अमरीका व्यापार वार्ता में तेजी आई थी। उसे रिपोर्ट्स में तेज गति से बातचीत के संकेत मिल रहे थे, ट्रंप का यह बयान कि भारत के सामान अभी भी कोई समझौता नहीं हुआ है, इस बाब का प्रमाण है कि भारत अमरीका के दबाव वाले सफलतापूर्वक सामाना कर रहा है। भारत अमरीका मुक्त व्यापार समझौते पर 2017 से चर्चा चल रही है। लेकिन अभी तक यह समझौता सिरे नहीं चढ़ पाया है, यहां तक कि सीमित स्तर पर भी नहीं। कई बार यह समझौता लगभग तय लग रहा था, लेकिन अचानक वह रुकावटें आ गईं और बातचीत ठंडे बस्ते में चार्चा गई। आखिरी बार ऐसा 2020 में हुआ था, मीडिया में खबरें आ रही थीं कि भारत-अमरीका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, लेकिन तब भी भारत ने दबाव का विरोध किया और संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसस्टीआर) को अपना भारत दें रह करना पड़ा। मौजूदा वार्ताओं में अमरीकी मांग कर रहा है कि भारत उसकी जीएम फसलों के लिए बाजार पहुंच दे, चिकित्सा उपकरण पर नियमों में ढील दी जाए और डेटा के मुकाबले प्रवाह की अनुमति दी जाए।

वास्तविकता यह है कि भारत अपने किसी और कृषि सुरक्षा के महेनजर जीएम के आय की अनुमति नहीं दे सकता और न ही आय विकित्सा उपकरण उद्योग के विरुद्ध अमरीकी नीतियों में से एक है।

निशाने पर ले रहे हैं। भारत पर पच्चीस फोसद टैरिफ लगाने का फैसला पहले ही सुना चुके हैं। अब चौबीस घंटों के भीतर इससे कहीं ज्यादा टैरिफ लगाने की उनकी धोषणा एक और चेतावनी है। ट्रॉप ने भारत के रूस से तेल खरीदने को वॉर मशीन की मदद करने सरीखा बताया है। भारत ने तत्काल इसे तर्कहीन बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका भी रूस से परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साप्लोराइड और इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता है।

कड़े प्रतिबंधों के बावजूद अमारका ने तकराबन साढ़े

तीन अरब डॉलर का रूसी गुड्स ट्रेड किया है। भारत सरकार ने भी स्पष्ट किया कि वैश्विक बाजार को स्थिर करने के लिए अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदते रहने को प्रोत्साहित किया गया था। मोदी को मित्र बता कर गलबहियां करने वाले ट्रंप के बदलते तेवर कूटनीतिक रूप से हताशा भरे माने जा सकते हैं। उन्होंने भारत को अच्छा व्यापारिक साझेदार न बता कर संदेह को भी बढ़ाने का काम किया है। रूस से सिर्फ तेल खरीद ही असल मुद्दा नहीं है। अमेरिका को भारत का रूसी सैन्य उपकरण लेना भी अखरता रहा है। अमेरिका के दबदबे को घुड़की देकर भारत ने वैश्विक समुदाय के समक्ष पश्चिमी देशों की पाखंड वाली नीति पर प्रश्न चिह्न लगाने में भी गुरेज नहीं किया। यूक्रेन में रूस के खिलाफ प्रॉवॉक्सी वॉर कर रहे गुटों की बात की जाए या व्यापार की तो इसकी किसी पारदर्शी योजना का अब तक खुलासा नहीं हुआ है।

साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा संभावित है। तब भी अमेरिका अपनी आक्रामकता पर काबू करने में

विफल रहने वाला है। खुद को शांति दूत के तौर पर पेश करने की ट्रूप की तमाम कोशिशों को दुनिया भली-भाँति देख रही है। भारत न सिर्फ विशाल बाजार है, बल्कि उसे अन्य मुल्कों के साथ साझीदारी/व्यापार करने से रोक पाना आसान नहीं है। उसे अपनी बढ़ती अर्थव्यस्था की गति को स्थिर रखने और घेरेलू दबावों के चलते अपने रुख पर कायम रहना होगा। ट्रूप की भभकी का असर अधिक इसलिए भी नहीं रह जाता क्योंकि वे अस्थिर व्यक्ति हैं उनके बयानों/विचारों में ढुलमुलाहट के चलते घबराने की

| तनिक आवश्यकता नहीं है।

# शिव के तांडव नृत्य का सिलसिला अभी भी जारी

प्रमोद भार्गव

भगवान भोले नाथ का गुरुस्सा प्रतीक रूप में मौत के तांडव नृत्य में फूटता है। देवभूमि उत्तराखण्ड में शिव के इस तांडव नृत्य का सिलसिला केदारनाथ में 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से अभी भी जारी है। उत्तरकाशी जिले की खीर गंगा नदी और धराली में बादल फटने और हँसलि के तेलगाड़ नाले में बाढ़ आने से बड़ी तबाही हुई है। धराली में 50 से ज्यादा घर, 30 होटल और 30 होमस्टे मलबे में बदल गए। जो खीर नदी 10 मी. चौड़ी थी, वह जल प्रवाह से 39 मी. चौड़ी हो गई। अतएव जो भी सामने पड़ा उसे लीलती चली गई। प्रशासन चार लोगों की मौत और 100 से अधिक लोगों के लापता होना बता रहा है। लेकिन हिमालय के बीचोंबीच बसे खूबसूरत धराली गांव में सैलाब जैसे नीचे उत्तरते दिखा, उससे लगता है कि मौतें कहीं अधिक हुई हैं। पलय इतनी तीव्रता से आई कि उसकी कान के पर्दे फाड़ देने वाली गर्जना सुनने के बाद लोगों को बचने का समय ही नहीं मिल पाया।

बादल फटना अनायास जरूर है, लेकिन ये करीब 10 किमी. व्यास की परिधि में फटने के बाद अति वृष्टि का कारण बनते हैं। 10 सेंमी. या उससे अधिक बारिश को बादल फटने की घटना के रूप में पारिभाषित किया जाता है। बादल फटने की घटना के दौरान किसी एक स्थान पर एक घंटे के भीतर उस क्षेत्र में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा की 10 प्रतिशत से अधिक बारिश हो जाती है। मौसम विभाग वर्षा का पूर्वानुमान कई दिन या माह

बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं। भू-स्खलन के अलावा इन दरारों की वजह कालिंदी और असिंगंगा नदियों पर निर्माणाधीन जल विद्युत और रेल परियोजनाएँ भी हैं। उत्तराखण्ड जब स्वतंत्र राज्य नहीं बना था, तब इस देवभूमि क्षेत्र में पेड़ काटने पर प्रतिबंध था।

नदियों के तटों पर होटल नहीं बनाए जा सकते थे। निजी आवास बनाने तक पर रोक थी। लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग होने के साथ ही केंद्र से बेहिसाब धनराशि मिलना शुरू हो गई। इसे ठिकाने लगाने के नजरिए से स्वयंभू टेकेदार आगे आ गए। उन्होंने नेताओं और नौकरशाहों का एक मजबूत गढ़जोड़ गढ़ लिया और नये राज्य के रहनुमाओं ने देवभूमि के प्राकृतिक संसाधनों की लूट की खुली छूट दे दी। दवा कंपनियां औषधीय पेड़-पौधों और जड़ी-बूटियों के दोहन में लग गई हैं। भागीरथी, खीरगंगा और अलंकनदा के तटों पर बहुमंजिला होटल और आवासीय इमारतों की कतार लग गई है। पिछले 25 साल में राज्य सरकार का विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन के अलावा कोई उल्लेखनीय काम नहीं है। जबकि इस राज्य का निर्माण का मुख्य लक्ष्य था कि पहाड़ से पलायन रुके। रोजगार की तलाश में युवाओं को महानगरों की ओर ताकना न पड़े। लेकिन 2011 में हुई जनगणना के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार पौदी-गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों की तो आबादी ही घट गई है। तथा है,

क्षत्र म पलायन आर पछड़ापन बढ़ा ह।  
विकास की पहुंच धार्मिक स्थलों पर ही सीमित रही है, क्योंकि इस विकास का मकसद महज श्रद्धालुओं की आस्था का आर्थिक दोहन रहा था। यही वजह रही कि उत्तराखण्ड के 5 हजार गांवों तक पहुंचने के लिए सड़कें तक नहीं हैं। खेती आज भी विश्वा पर निर्भर है। उत्पादन बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधाएं नदारद हैं। तिस पर भी छोटी-बड़ी प्राकृतिक आपदाएं कहर ढाती रहती हैं। इस प्रकोप ने तो तथाकथित आधुनिक विकास को मिट्टी में मिला कर जल के प्रवाह में बहा दिया है। ऐसी आपदाओं की असली चुनौती इनके गुजर जाने के बाद खड़ी होती है, जो अब जिस भयावह रूप में देखने में आ रही है, उसे संवेदनशील आंखों से देखा जाना भी मशिकल है। (गढ़ देवत के आने विज्ञा है)



# शहर में सबसे ज्यादा कवर्ड कॉलोनियों में चोरी: क्योंकि गार्ड रोक टोक नहीं कर रहे, सीसीटीवी कैमरे बंद, पुलिस पेट्रोलिंग भी कम

रायपुर, 13 अगस्त (एजेंसी)। शहर में लोग बेहतर और कड़ी सुरक्षा के लिए कवर्ड कॉलोनियों में लाखों-करोड़ रुपए खर्च कर मकान खरीद रहे हैं। लेकिन अभी इन्हीं कवर्ड कॉलोनियों में चोरी की घटनाएं बहुत गई हैं। पुलिस ने इनके लिए कवर्ड कॉलोनियों के अनुसार ही रह फैले और सतन दो चोरों द्वारा कवर्ड कॉलोनियों में हो रही है। इस कवर्ड कॉलोनी के लिए हैं कॉलोनी में किसी भी समय आओ-जाओ वे कोई रोक-टोक नहीं करते हैं। कवर्ड कॉलोनियों के सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। इस बजह से चोरी के बाब पता ही नहीं चलता कि चोरी आखिर कैसे और किसने की। इनमें चोरी नहीं रहते हैं। इन सीसीटीवी कैमरों में चोरी हो गई है। राजधानी में अभी 3 अगस्त को तीन कवर्ड कॉलोनी स्टर्टिंग हीम सोबत थोरीक, रायल रेजेस्ट्री और हिंगालन लाइट्स के 5 प्लैट में केवल छह घंटे के भीतर चोरी हो गई साइंस सेंटर के पीछे इवान को सोसायटी में साइकिल के लिए चोरी हो गई। इन सोसायटी में पुलिस नाकाम पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर तब नोट नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों की टीम शहर की अलग-अलग 13 सोसायटीयों में पहुंची। किसी भी कॉलोनी में रात 11 से 20 बजे तक किसी ने नहीं रोका। कई जगहों पर मूल्य प्रवेश द्वारा पर सुरक्षा गार्ड मिले, लेकिन किसी भी



संवाददाता की गाड़ी नहीं रोकी। रिपोर्टर आराम से कॉलोनी में दाखिल हो गए। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की गई तो पता चला कि वो खराब है। अधिकतर जगहों पर पूरे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। भासकर टीम ने अशोका रतन, कैपिटल होम, कैपिटल सिटी, सफायर ग्रीन, मौलश्री विहार, फाफाडी रोड में स्थित कॉलोनियों, शेकरनगर के कवर्ड अपार्टमेंट समेत कई जगहों की जांच की। कुछ कॉलोनियों में भासकर रिपोर्टर हेलिमेंट लगाकर गए। चेहरा नहीं दिखाने के बावजूद गार्ड नहीं रोका। रिपोर्टर ने सोसायटी के भीतर एक राउंड लगाया। कुछ देर रुकने के बाद निकल गए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और रायपुर विकास

प्रधिकरण की कवर्ड कॉलोनियों और अपार्टमेंट का और भी बुरा हाल मिला। आरडीए के रायपुर स्थित इंद्रप्रस्थ फेस वन और दूर बारियाकला और बारियाखुर्द में स्थित कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड की सरोना, कचना, सहु और सेजबहान में स्थित कॉलोनियों में सुरक्षा के कोई इंजाम नहीं है। इन सभी जगहों पर कोई भी भी आज-आज सकता है। कई कॉलोनियों में गार्ड भी भी आज-आज जगहों पर ही रहते हैं। इन सभी जगहों पर कोई भी कॉलोनी में बदल दिया। घटना के लोगों से बात की तो पता चला कि सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं। जहां लगाए गए वो कई महीनों से खराब हैं। इन्हें ठीक तक नहीं कराया गया है। कॉलोनी में किसी भी किसके लोग आसानी से आना-जाना कर रहे हैं ऐसा जान्हानी में रात की पुलिस बेटेलिंग के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल पर ही क्षमा कर दिया, जिससे मार्ग वाली की लंबी कतारें लग गईं। टीम, जिसमें एसडीएम शिवानी जायसवाल और तसीलीदार शामिल थे, मौके पर पहुंची। उन्होंने लोगों से बातचीत कर माहौल को शांत किया और पीड़ित परिवार को 25 हजार रुपए की ताकालिक सहायता राशि प्रदान की। इस दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब कर लिया है और चालक के खिलाफ कामाल दर्ज कर लिया गया है। वहां स्थानीय लोगों और जनप्रियनिधियों ने भाग की है कि स्कूल समय और सामाजिक बाजार के दौरान भारी वाहनों की आवाज नहीं जाए। भाजयुगों में डूपथक्ष अनूप जायसवाल ने भी दिन में कोयला परिवाह पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तहत की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। यह हादस न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है। यह सवाल अब गंभीरता से उठाया जा रहा है कि क्या भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए, खासकर रिहायशी और सेवेदशील इलाकों में।

## भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत पती और मासूम बेटा घायल

सूरजपुर, 13 अगस्त (एजेंसी)। रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व के दिन सूरजपुर जिले में एक दर्दनाक हादस सामने आया, जिसने पूरे क्षेत्र को झक्कड़ा कर रख दिया। बिश्रामपुर-दतिया मार्ग पर रायपुर सप्तराम निवासी द्वारा गार्ड रोक-टोक कर नहीं करते हैं। कवर्ड कॉलोनियों के सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। इस बजह से चोरी के बाब पता ही नहीं चलता कि चोरी आखिर कैसे और किसने की। इनमें चोरी हो गई है। राजधानी में अभी 3 अगस्त को तीन कवर्ड कॉलोनी स्टर्टिंग हीम सोबत थोरीक, रायल रेजेस्ट्री और हिंगालन लाइट्स के 5 प्लैट में केवल छह घंटे के भीतर चोरी हो गई साइंस सेंटर के पीछे इवान को सोसायटी में साइकिल के लिए चोरी हो गई है। इन सोसायटी में पुलिस नाकाम पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर तब नोट नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सोसायटीयों में गए। गेट पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नंबर नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सोसायटीयों में गए। गेट पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नंबर नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सोसायटीयों में गए। गेट पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नंबर नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सोसायटीयों में गए। गेट पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नंबर नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सोसायटीयों में गए। गेट पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नंबर नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सोसायटीयों में गए। गेट पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नंबर नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सोसायटीयों में गए। गेट पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नंबर नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सोसायटीयों में गए। गेट पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नंबर नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सोसायटीयों में गए। गेट पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नंबर नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सोसायटीयों में गए। गेट पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नंबर नहीं किया गया। कॉलोनी में धूसकर धरों के ताले तोड़कर कैश व जेवर लेकर भाग गए। इसी तरह की चोरी हर फैले हो रही है। अपार्टमेंट, कॉलोनी या कवर्ड कॉलोनियों में हो रही चोरी को रोकने में पुलिस नाकाम है। रिपोर्टों के लिए धूमने वाली गार्ड खुट्टा थे। इस बजह से चोरी हो गई है। चोर आराम से इन सो



